नागरिक समाज के हस्तक्षेप से चल रही परियोजनाएं

भारत में गैर सरकारी संगठनों की अगुवाई में अनेक परियोजनाओं को 2003 के बाद से एचआईवी/एड्स से लड़ने के लिए 75 लाख यूरो की सहायता दी गयी है। अंतरराष्ट्रीय एवं स्थानीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा लागू की जा रही इन परियोजनाओं के उद्देश्य इस प्रकार हैं–

- विशेष रूप से ग्रामीण एवं जनजातीय समुदायों में जोखिम वाले युवाओं तक पहुंच बनाना।
- लैंगिक अल्पसंख्यकों की सामाजिक जरूरतों और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का समाधान करना।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं में एचआईवी/एड्स की रोकथाम के उपाय करना।
- जोखिम वाली महिलाओं के लिए यौन और प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना।
- युवाओं और किशोरों के स्वास्थ्य के लिए अधिकार आधारित कार्यों को बढ़ावा देना।
- एचआईवी/एड्स ग्रस्त लोगों और विकलांगों को बहिष्कृत रखने के मुद्दों का समाधान करना।
- मलेरिया, टीबी और एचआईवी की अधिकता वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी अधिकार सुनिश्चित करना।

अनुदान तक पहुँच

यूरोपीय आयोग ऑन लाइन प्रस्ताव आमंत्रित करता है और उसके माध्यम से अनुदान लेना सम्भव है। नीचे दी गयी वेबसाइट नियमित ताजा जानकारी देती है और सभी विवरण उपलब्ध कराती है।

http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm

सभी प्रस्तावों के उम्मीदवारों को एक समय सीमा के भीतर काम के प्रस्ताव देने को कहा जाता है और उनके उद्देश्य पूछे जाते हैं। सभी आवेदनों की जांच और मूल्यांकन प्रस्तावों की घोषणा के समय निर्धारित पैमानों के आधार पर की जाती है और सभी के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाता है।

नागरिक समाज की पहल के लिए अनुदान के अवसरों की जानकारी नीचे दिए गए वेबसाइट पते पर उपलब्ध है।

http://ec.europa.eu/europeaid/who/partner/civil-society/programmes_en.htm

फोटो क्रेडिट: ऑक्सफेम जीबी, एचआईवीओएस

यूरोपीय संघ

भारत के लिए प्रतिनिधिमंडल
65 गोल्फ लिंक्स, 110003 नयी दिल्ली
फोनः +91–11–24629237, 24629238
फैक्सः +91–11–24629206
वेबसाइटः www.delind.ec.europa.eu

यूरोपीय संघ

भारत में एचआईवी/एड्स से संघर्ष

भारत में एचआईवी/एड्स – बदलता स्वरूप

ईयू की मजबूत प्रतिबद्धता

यूरोपीय संघ दुनियाभर में एड्स की महामारी से सामने आयी असाधारण चुनौती से निपटने के लिए मजबूती से प्रतिबद्ध है और इसके लिए वह दीर्घकालिक साझेदारी और रणनीतिक प्रयासों से आने वाले दशकों में स्थायी प्रगति को सहारा दे रहा है।

एचआईवी/एड्स, मलेरिया और ट्यूबरक्यूलोसिस पर नियंत्रण करने संबंधी ईयू के कार्यक्रम (2007–2011) के तहत एचआईवी/एड्स को नियत्रंण करने का मकसद प्राथमिक है और इसमें राष्ट्रीय विकास योजनाओं और कार्यक्रमों का समन्वय किया जा रहा है लेकिन साथ ही स्वामित्व के सिद्धांत का पूरी तरह आदर किया जाता है।

ईयू ने एड्स की महामारी पर काबू पाने के लिए तुरंत राजनीतिक नेतृत्व के हस्तक्षेप और एचआईवी रोकथाम कार्यक्रमों में निवेश की आवश्यकता जाहिर की है। ईयू इस महामारी के कारकों से निटपने के लिए प्रतिबद्ध है। यह चिंता की बात है कि एचआईवी ग्रस्त लोगों को कलंकित माना जाता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ईयू उनके मानवाधिकारों और स्वतंत्र रूप से आवागमन के अधिकार के लिए वचनबद्ध है।

एड्स, मलेरिया और ट्यूबरक्यूलोसिस से लड़ने के लिए विश्व कोष

एड्स, तपेदिक और मलेरिया से लड़ाई के लिए विश्व कोष स्थापित होने के बाद से ही ईयू उसके सभी संचालन निकायों में सक्रिय है। **इस फंड के बोर्ड में ईयू की सीटें** दानदाता के तौर पर है जिनमें यूरोपीय आयोग और सदस्य देश (बेल्जियम, पुर्तगाल और फिनलैंड) शामिल हैं।

इस कोष के लिए **ईयू परम्परागत रूप से कुल योगदान का 50 प्रतिशत उपलब्ध करा रही है।** ईयू सदस्यों का योगदान बढ़ने से 2006 के बाद से लगातार ईयू का हिस्सा बढ़ रहा है। अगले तीन साल में ईयू इस फंड में 60 प्रतिशत योगदान करेगी।

भारत में एचआईवी/एड्स संबंधी कुल 595,784,582 डॉलर (414 मिलियन यूरो) ग्लोबल फंड अनुदान में **ईयू का आधे से अधिक योगदान** है।

राष्ट्रीय नीतियों में नागरिक समाज का अंशदान

एचआईवी/एड्स से लड़ने के लिए नागरिक समाज के हस्तक्षेप में ईयू भारत की राष्ट्रीय नीतियों में पूरक के तौर पर समर्थन दे रही है।

सभी पक्षों को मंच देने के लिए इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 5 मार्च, 2008 को एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) के अलावा ईयू अनुदान वाली एजेंसियों, विकास सहयोगियों एवं नागरिक समाज को शामिल किया गया।

विचार–विमर्श का केंद्र रोग के संकेतकों और निगरानी साधनों पर था। एनएसीओ और ईयू प्रायोजित 9 परियोजनाओं की ओर से इसमें प्रस्तुति दी गयी और इस बात को उजागर किया गया कि किस तरह संकेतकों पर नजर रखने और मजबूत एवं एक समान आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली से राष्ट्रीय नीतियों एवं प्राथमिकताओं से जुड़ने में मदद मिलती है।

http://www.delind.ec.europa.eu/en/dev/hiv-aids_sem/hiv-aids.htm